

40 नं. 5/08-2016.8 -

8 नं. 08/08 ✕

संख्या: भा०स०/16/43-2-2008-15/2 (7)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

SC-24

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ ; दिनांक 14 जुलाई 2008

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अंतर्गत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरण (Public Authority) का जन सूचना अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के द्वारा उसे सौंपे गये कार्यों के निर्वहन में हुई चुट्टियों के अतिरिक्त पर शास्त्रित लगाई जा सकती है। अतः जन सूचना अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि यह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसके प्रावधानों को भली भाँति समझे। भारत सरकार द्वारा जन सूचना अधिकारियों के कार्यों के सम्बन्ध में अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग की प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/ संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के प्रत्येक लोक प्राधिकरणों में नामित जन सूचना अधिकारियों को मार्ग दर्शिका की एक-एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

25/7/08

जन सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिका का किसी भी "लाक पाधिकरण" (Public Authority) से सूचना प्राप्त करने का अधिकार पदान करता है। किसी लाक पाधिकरण का जन सूचना अधिकारी नागरिका के सूचना के अधिकार को मृत रूप देने में मुख्य भूमिका निभाता है। अधिनियम उस विनिश्चित कार्य सापता है और किसी त्रुटि के मामले में उसे भास्ति हंत जवाबदेह ठहराता है। अतः जन सूचना अधिकारी के लिए यह आव यक है कि वह अधिनियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और इसके पावधाना का भली-भांति समझ।

सूचना क्या है

2. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामगी "सूचना" है। इसमें किसी भी इलक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, पंस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदि, लांगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमून, माडल, आंकडा सम्बन्धी सामगी शामिल है। इसमें किसी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना भी शामिल है जिस लाक पाधिकरण तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

3. किसी नागरिक का किसी लाक पाधिकरण (Public Authority) से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जा उस लाक पाधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लाक पाधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कति, दस्तावेजा तथा रिकाडा का निरीक्षण, दस्तावेजा या रिकाडा के नाट, उद्धरण या पमाणित पतियां प्राप्त करना, सामगी के पमाणित नमून लेना शामिल है।

4. अधिनियम नागरिका का, संसद-सदस्या और राज्य विधान मण्डल के सदस्या के बराबर सूचना का अधिकार पदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिस संसद अथवा राज्य विधानमण्डल का देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उस किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

5. नागरिका का डिस्कटस, फलापी, टप, वीडिया कंसट या किसी अन्य इलक्ट्रॉनिक रूप में अथवा पिट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ब ता कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी व्यक्ति में पहले से सुरक्षित है, जिससे उस डिस्कट आदि में स्थानांतरित किया जा सक।

